BAKHT): (a) The Delhi Administration is drawing up a plan with regard to the construction of lawyers' chambers by the lawyers themselves in the Districts Courts area in Delhi.

(b) No, Sir.

(c) Question does not arise.

Reintroduction of Crop Insurance

3816. SHRI KUMARI ANANTHAN: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Government have received representations from various State Governments and M.Ps. for the introduction of crop Insurance Scheme in the country to assist farmers; and

(b) if so, the steps taken by Government in this direction?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) and (b). The Government of India have been receiving representations for the introduction of crop insurance scheme to assist farmers. At the instance of Government of India, the General Insurance Corporation had implemented experimental crop insurance schemes for selected crops in selected areas during 1973—76, on a voluntary basis. These schemes were found uneconomic and also unsuitable for implementation on a larger scale.

राष्ट्रीय कृषि आयोग का प्रतिवेदन

3817. श्री [illegible] प्रसाद यादव: क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषि आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया; और

(ख) सरकार का उस पर क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) राष्ट्रीय कृषि आयोग ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट 31 जनवरी, 1976 को प्रस्तुत की थी ।

(ख) आयोग की सिफारिशों का संबंधित मंत्रालयों द्वारा विश्लेषण करने और उन पर कार्यवाही करने का कार्य जारी है । सिफारिशों पर कार्यवाही करने के कार्य में सहायता देने, समन्वय करने और क्रियान्वयन की प्रगति का समय समय पर पुनरीक्षण करने के लिये कृषि विभाग में एक क्रियान्वयन सेल की स्थापना की गयी है ।

राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने से संबंधित सिफारिशों को कार्य रूप दें । उन्हें ऐसी कई सिफारिशों पर कार्यवाही करने को कहा गया है, जिन पर राज्यों द्वारा कार्यवाही की जानी है और जिनके लिए केन्द्र की सामान्य सहमति प्राप्त है । इन प्रयत्नों के फलस्वरूप सिफारिशों के क्रियान्वयन में काफी प्रगति हुई है । सरकार द्वारा अब तक कुल सिफारिशों में से एक चौथाई से अधिक को स्वीकार किया जा चुका है और इन्हें या तो राज्यों को क्रियान्वयन के लिये भेज दिया गया है अथवा उन्हें क्रियान्वित करने के लिये कार्यवाही आरम्भ/पूरी कर दी गई है । अन्य सिफारिशों के बारे में कार्यवाही की जानी है । राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों पर आधारित कार्यक्रमों के लिये कृषि विभाग के वर्ष 1977-78 के बजट में लगभग 29 लाख रुपए की सांकेतिक व्यवस्था की गई है । राज्य सरकारों को उपयुक्त योजनाएं/कार्यक्रम तैयार करने और उन्हें राज्यों की योजनाओं में शामिल करने की सलाह भी दी गई है ।